



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 588]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 1985/अग्रहायण 19, 1907

No. 588] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 1985/AGRAHAYANA 19, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1985

रा. प्रा. २९३(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के
खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु, भारत सरकार
(कार्य आर्बंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्न-
लिखित नियम बनाने है। अर्थात्:—

1 (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आर्बंटन)
(एक और संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये शब्द प्रयुक्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(i) शीर्षक "1.2 कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और
शौक शिवालय तथा पेंशन मंत्रालय" के स्थान पर निम्नलिखित
शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1.2 कार्मिक, शौक शिवालय तथा पेंशन मंत्रालय।",

(2) शीर्षक "1.4 परिवहन मंत्रालय" के नीचे उप-शीर्षक

"(i) रेल विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्षक
रखा जाएगा, अर्थात् —

"(i) रेल विभाग (रन ब्रोड), "

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(i) शीर्षक "डॉ. मंत्रालय" के नीचे —

(क) उपशीर्षक "1. कृषि और सहायता विभाग" के नीचे भाग
4 की पैरिफ्ट 14 में "योग्य वन विभाग" शब्दों का लोप
किया जाएगा।

(ख) उपशीर्षक "ख कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग" के नीचे

(1) भाग 1 की पैरिफ्ट 1 में "विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय
कृषि गवेषणा और शिक्षा संस्थानों और संगठनों से संबंध"
शब्दों के स्थान पर "कृषि अनुसंधान और शिक्षा के
क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जिसके अन्तर्गत विदेशी
और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि, अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों
और संगठनों से संबंध भी है" शब्द रखे जाएंगे।

(2) प्रविष्टि 2 में "वृषि पशुपालन, डेरी उद्योग और मीन उद्योग में उत्तमतर शिक्षा" शब्दों के स्थान पर "वृषि जिनके प्राप्ति वृषि नापिकी थी है, पशुपालन, डेरी उद्योग और मीन उद्योग में उत्तमतर शिक्षा" अन्तर्भूत रखे जाएंगे।

(ग) उपशीर्षक "ग. ग्रामीण विकास विभाग" के नीचे प्रविष्टि 19 के पर्याप्त निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्—

"19क असम के उन जनजात क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित कार्य सम्भाला जा सविधान की छठी अनुसूची के प्रा. 24 से स्थापित सार्वजनिक सेवाओं के भाग 1 और 2 में निर्दिष्ट है"

(2) शीर्षक "वाणिज्य मन्त्रालय" के नीचे उपशीर्षक "ग. ग्रामीण विकास विभाग" के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्—

"1. उन क्षेत्रों से, जिनमें कृषि और पशुपालन का नियंत्रण किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यापनित किया गया है, निम्न मामलों का केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय विभाग, जिसके अन्तर्गत उसके सम्बद्ध और अखिल भारतीय और स्थानीय क्षेत्र भी है, के लिए कृषि और/या निरीक्षण।

2. उन राज्य सरकारों, लोक उद्यमों स्थापित निगमों और सरकारी निगमों आदि की ओर से मामलों या कृषि और/या निरीक्षण या इसकी सेवाओं का फायदा उठाना आदि।

3. उपर 1 और 2 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों की ओर से विभाग (पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय) द्वारा रखी गई सविधान के संबंध में किए गए प्रदायों के लिए न्याय की व्यवस्था करना।

4. विभाग द्वारा दिए गए आदेशों और अन्य केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, स्थापित निगमों आदि द्वारा दिए गए आदेशों के संबंध में प्राधिकारित मामलों की निरीक्षण की व्यवस्था करना, यदि ऐसा करने के लिए कहा जाए। जहाँ प्राधिकारित विभाग द्वारा दी गई सविधानों के संबंध में या जहाँ ऐसा कहा विभागों का प्रत्यक्ष प्राधिकारियों द्वारा सौंपा जाए वहाँ मामलों की निरीक्षण की व्यवस्था करना।

5. ऐसी मामलों का व्ययन जो उनमें निम्न निम्नलिखित विभिन्न प्राधिकारियों साधारण या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रत्यापनित की गई हैं।

6. मामलों, उदाहरणों, उदाहरणों और पशुपालन की व्यवस्था और मूल्यांकन, जाच प्रीविलेज सेवा सविधान के 2 में प्रत्यक्ष और 'व्याप्त तथा सोपानक II के अन्तर्गत या अन्य प्रकार से प्राधिकारों का अन्तर्गणन।

7. भारतीय पूर्ति सेवा का सर्वोच्च प्रबंधन और उन्नत सेवा के लिए प्रविष्टि बृत्ति योजना और जनशक्ति योजना से संबंधित मामलों विभाग।

8. भारतीय निरीक्षण सेवा का सर्वोच्च प्रबंधन और उन्नत सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना या सर्वोच्च से विभाग।

9 निम्नलिखित का प्रमाण—

(क) पूर्ति और व्याप्त सेवा सविधान में विभाग।

(ख) मुख्य सेवा नियंत्रण का कार्यालय, नई दिल्ली।

(ग) राष्ट्रीय जाच मन्त्र, प्रीविलेज कलकत्ता।

(3) "संचार मन्त्रालय" शीर्षक के नीचे,—

(क) उपशीर्षक "क. डाक विभाग" के नीचे, प्रविष्टि 3 में, "डाक-घर और जीवन बीमा निधि (प्रमाणन) प्रमाणन और पाही अनु-

ज्ञान" शब्दों के स्थान पर "और डाकघर जीवन बीमा निधि (प्रमाणन)" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपशीर्षक "दूरगन्तार विभाग" के नीचे मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"4. मन्त्रालय के निदेशों द्वारा निर्मित बंगलौर, हिन्दुस्तान टेलिफोन लिमिटेड मद्रास और टेलिफोनिकेशन कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड नई दिल्ली।"

(3) शीर्षक "रक्षा मन्त्रालय" के नीचे,—

(क) उपशीर्षक "रक्षा विभाग" के नीचे, मद 13 के पर्याप्त निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"11 रक्षा लक्ष्य विभाग।

15 निम्नलिखित का प्रमाण—

(1) सेना पेशन विनियम, 1961 (भाग 1 और भाग 2)

(2) वायु सेना पेशन विनियम, 1961 (भाग 1 और भाग 2)

(3) नौसेना पेशन विनियम, 1964, और

(4) मण्डल वन समितिके दुर्घटना पेशन प्रदाय हकदारी नियम, 1982

16 वैदिक आस्थापनाओं के लिए खाद्य सामग्रियों का कृषि उत्पाद प्रोत्साहन या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय (खाद्य विभाग) को सौंपे गए हैं।

17 रक्षा मण्डल।

(ख) उपशीर्षक "रक्षा मन्त्रालय और पूर्ति विभाग" के नीचे,—

(1) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"1. गोला बारूद कारखाना जोड़े और गोलाबारूद कारखाना।",

(2) प्रविष्टि 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्—

"5. गार्डन रीड लिमिटेड मद्रास इजीनियर्स लिमिटेड।

6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।

6क. प्रागा टम लिमिटेड।

6ख. भारत टायनामाइड लिमिटेड।

6ग. मिश्र गन्त निगम लिमिटेड।

6घ. रक्षा निरीक्षण मण्डल।

6ज. रक्षा उद्योग तथा सामग्रियों का मानकीकरण।",

(3) प्रविष्टि 9 में "परमाणु ऊर्जा विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्—

"ऊर्जा विभाग

(1) प्रविष्टि 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्—

9. परदेशीकरण विकास और रक्षा प्रयोजनों के अपेक्षित विकास का प्रमाण।

10. रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरण।",

(2) शीर्षक "ऊर्जा मन्त्रालय" के नीचे उपशीर्षक "ख. विद्युत विभाग" के नीचे प्रविष्टि 10 और 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्—

"10. माधुवा व्यास प्रबंध बोर्ड और व्यास मन्त्रिमणि बोर्ड (सिन्हाई से सञ्चित विषयों को छोड़कर)

11. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड।

12. राष्ट्रीय जन विद्युत निगम लिमिटेड ।
13. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ।
14. उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड ।
15. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ।
16. विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण समाइट । ,

(6) शीर्षक 'पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के नीचे शीर्षक 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

17. वानिकी विकास स्कीमों को विनियम गहायता । "

(7) उचित विदेश मंत्रालय के नीचे —

- (क) प्रविष्टि 5 के द्वितीय पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है
- (ख) प्रविष्टि 11 में 'स्वच्छ वाता माहिरा शब्द और 'ओर दशा में भारत जाने वाले' शब्दों का वापस लिया जाएगा
- (ग) प्रविष्टि 19 में 'और अन्य अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन शब्दों स्थान पर अन्य अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन और सम्मेलन शब्द रखे जाएंगे ,
- (घ) प्रविष्टि 25 (F) में 'पाठ हज समिति अधिनियम 1932' शब्दों और अक्षरों के स्थान पर 'हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51)' शब्द अक्षरों और काष्ठक रखे जाएंगे ,
- (ङ) प्रविष्टि 27, 28 और 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"27 पड़ोसी देशों में अस्पष्टता से सम्बन्धित प्रश्न ।";

(8) 'विनय मंत्रालय' शीर्षक के नीचे,—

- (क) उप शीर्षक "क आर्थिक तथा विमान" के अधीन प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् —

"I मुद्रा नियंत्रण

1. राजस्व विभाग के अधीन वर्तमान प्रवर्तन कार्य में मिला है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) का प्रशामन ।
2. विदेशी मुद्रा मन्त्री पाठ तैयार करना ।
3. रुपए की विनियम दर संबंधी नोंति ।
4. विदेशी मुद्रा स्थानों का नियंत्रण जिसमें विदेशी मुद्रा का रेट के आयातों की प्रस्थापना की मवीक्षा भी सम्मिलित है ।
5. विदेशी और अनिवासी भारतीय विनिमय ।
6. विदेशों में वाणिज्यिक उधार देने के लिए अनुमोदन जिसमें उसका निबन्धन और शर्तें भी सम्मिलित हैं ।
7. सोना और चांदी का आयात और निर्यात ।

II. आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता

8. निम्नलिखित से संबंधित बाने —

- (क) भारत कम्पैण्डम ।
- (ख) विदेशों में ऋण, उधार और आर्थिक सहायता ।
- (ग) पुर्ननिर्माण और विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंक से उधार और ऋण, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि, एशियाई विकास बैंक, परेपोय आर्थिक समुदाय और निर्यात-आयात बैंक आदि ।
- (घ) फोर्ड फाउंडेशन और रोकफेलर फाउंडेशन ।
- (ङ) कनाडा अन्तरराष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आई डी आर. सी.) ।

(न) कम्पैण्डम तकनीकी सहकारिता निधि (सी एफ टी सी)।

9. निम्नलिखित के अधीन भारत द्वारा प्राप्त तकनीकी और आर्थिक सहायता —

- (क) कोलम्बा योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम ।
- (ख) समुक्त राज्य का चार सूत्री कार्यक्रम ।
- (ग) संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन कार्यक्रम ।
- (घ) विभिन्न विदेशों में तकनीकी सहायता के तदर्थ प्रस्ताव ।

10. कोलम्बा योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम के अधीन कोलम्बा योजना के अन्तर्गत राजा का भारत द्वारा की गई तकनीकी सहायता और विशेष रूप से अफीम सहायता योजना कार्यक्रम के अधीन अफीम दवा का भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता ।

11. पाचम्बो योजना परिषद् और योजना के परामर्शदात समिति के अविदेशीता से संबंधित सभी मामले ।

12. भारत मुद्रा और वित्त विभाग को प्रोत्साहन अन्य देशों को भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण से संबंधित सभी मामले ।

13. भारत का प्राप्त होने वाला या विदेशी सरकारों, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों की ओर से दाली तकनीकी सहायता जिसमें वे नहीं हैं जिनका मन्त्र किसी अन्य विभाग का आवंटित विषयों से हो ।

14. समुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) से संबंधित सभी मामले जिसमें ऐसे कार्यक्रम या परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं जिन्हें यू.एन.डी.पी. बजट से निधि प्रदान की गई है ।

15. यूनाइटेड नेशन्स फंड फार पापुलेशन एस्टीमेटोज (यू.एन.एफ.पी.ए.) से संबंधित और राष्ट्र सभ के विशिष्ट अधिकारों तथा राष्ट्र सभ के अन्य निर्णयों के अन्तर्गत से संबंधित नीति संबंधी मामले ।

16. (यू.एन.डी.पी. अन्तर्गत बर्तमान बाल्टियर्स के अतिरिक्त) यूनाइटेड नेशन्स बाल्टियर्स सहित भारत में विदेशी बाल्टियर्स कार्यक्रम से संबंधित सभी मामले ।

III. आन्तरिक वित्त

17. राष्ट्रीय और विभाग निर्माण से संबंधित सभी । य (जिनमें निम्नलिखित भी हैं) —

- (क) प्रतिभूति और करमी मुद्रण करने वाले मुद्रणालय, सिक्कूरीटी प्रपर मिल और टकमाले (इसके अन्तर्गत परब विभाग और चांदी परिष्करण नाना परिष्करण और स्वर्ण संग्रहण सह परिष्करण केंद्र भी हैं) ।
- (ख) करमी नाट का त्रि त्रिणी और बैंक नोट तथा सिक्के, डाक लेखन सामग्री, स्टाम्प और विभिन्न प्रतिभूति प्ररूपों का उत्पादन और पुंति ।

18. भारत क पूरा विभागों के कोषपाल के कृत्य ।

19. प्रतिभूति मन्त्रि (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) का प्रशामन ।

20. स्टैंडर्ड एक्स्चेंज का विनियमन और विकास ।

21. समुक्त राष्ट्र कर्माना द्वारा जारी की गई पूंजी का नियंत्रण ।

22. राजी व भारत से सम्बन्ध प्राप्त करने के लिए नए विनिमय और प्रतिभूतियां ।

23. विनिमय नीति जिसके अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा नियम, भारतीय वनिट टस्ट और भारतीय वातावरण बीमा नियम की नीतियां भी हैं ।

24. कर्वाचारी मन्त्रि निधि और अन्य वैसी ही मन्त्रि निधियों की विनियमन ।

IV बजट

25. अर्थोपाय।

26. रेल बजट का विषय अनुपूर्व अतिरिक्त अनुदान भी है जो छोड़कर केन्द्रीय बजट तैयार करना और जब किसी राज्य अथवा राज्य क्षेत्र के संबंध में गवर्धनित तत्त्व की विफलता के कारण राष्ट्रपति की उद्घोषणा प्रवर्तनशील हो तात्वे राज्य अथवा क्षेत्र राज्य क्षेत्र का बजट तैयार करना।

27. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों तथा मंत्रालयों द्वारा भारतीय प्राप्त संस्थाओं के बाजारों पर कार्रवाई।

28. केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजारों में खण्ड का लिए जाता और खजाना हस्तियों का निर्माण और उत्प्रेषण।

29. लोक खण्ड अधिनियम, 1944 (1944 का 19) का प्रशासन।

30. केन्द्रीय सरकार के उधार लेने और खण्ड देने के संबंध में व्याज दरों का नियत किया जाना।

31. लेखा और लेखा परीक्षण प्रक्रियाएँ जिनके अन्तर्गत मध्यवर्ती का वर्गीकरण है।

32. विभाजन फेडरल वित्तीय एकीकरण और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित वित्तीय मामलों।

33. भारतीय आकस्मिकता निधि और भारतीय आकस्मिकता निधि का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 49)।

34. केन्द्रीय सरकार की बजट संबंधी स्थिति का अनुसंधान।

35. स्टालिंग पेंशन—यू.के. सरकार के उत्तरदायित्व का अंतरण और अंतर्गत दायित्व की वास्तविक धनना।

36. लोक भविष्य निधि स्कीम।

37. वित्त आयोग।

38. पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के स्रोत।

39. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय निक्षेप स्कीम, विशेष निक्षेप स्कीम, अनिवार्य निक्षेप स्कीम और अन्य निक्षेप स्कीम।

40. लघु बचत, जिनके अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत संगठन का प्रशासन भी है।

41. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ।

42. संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन संसद के समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश करना।

43. वित्तीय आपात।

V. प्रकीर्ण अधिनियम

44. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 (1973 का 5)

45. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 जो विनिश्चालन का व्यवस्थापन करती है।

46. घात मित्ता अधिनियम, 1889 (1889 का 1)।

47. पूर्ण विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6)।

48. भारतीय विकास निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3)।

49. भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 (1920 का 10)।

50. कुरेगी अध्यादेश, 1940 (1940 का 4)।

51. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945।

52. पूंजी निर्माण (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29)।

53. वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33)।

54. सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46)।

55. अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963 (1963 का 21)।

56. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52)।

57. वैयक्तिक निविदा (अन्तर्गत निविदा नोट) अधिनियम, 1964 (1964 का 29)।

58. गुणिगार्ह विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 18)।

59. लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23)।

60. छोटें सिकके (प्रपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52)।

61. नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 54)।

62. अतिरिक्त उपवास्यता (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37)।

63. अफीकी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 1)।

64. अफीकी विकास बैंक अधिनियम, 1983 (1983 का 13)।

VI बीमा प्रमाण

65. साधारण बीमा, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और साधारण बीमा कारखाना (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) का प्रशासन, साधारण बीमा निगम की शमनुधनियों से संबंधित नीति।

66. जीवन बीमा, जीवन बीमा कारखाना का राष्ट्रीयकरण, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) का प्रशासन, जीवन बीमा अधिकरण से संबंधित नीति।

67. बीमा नियंत्रक।

68. 65 से 67 तक की किसी भी प्रविष्टि की बावत केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से संबद्ध मामलों के विषय में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व।

VII. भारतीय आर्थिक सेवा का प्रबंध

69. भारतीय आर्थिक सेवा के प्रबंध के केन्द्रीय पहलू और उस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जनशक्ति योजना से संबंधित सभी मामले।

VIII. आर्थिक सहाय

70. उन मामलों पर सहाय जो आर्थिक प्रबंध जिसके अंतर्गत मूल्य भी हैं, के आर्थिक और बाह्य पहलुओं से संबंधित हैं।

71. खण्ड, वित्त और मुद्रा संबंधी नीतियाँ।

IX. बैंककारी

72. सभी भारतीय बैंक चाहे वे राष्ट्रीयकृत हो या नहीं।

73. सभी विदेशी बैंक जहाँ तक भारत में उनकी संस्थाओं का संबंध है।

74. भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सभी मामले।

75. सहकारी बैंककारी से संबंधित सभी मामले।

76. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट या कृषि, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम की छोड़कर दीर्घकालिक वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सभी मामले।

77. लिटफंड और निक्षेप खोलावर करने वाली अन्य गैर-बैंककारी कंपनियाँ।

78. भारत में बैंककारी से संबंधित अन्य मामले ।

79. उपर्युक्त 72 से 78 प्रविष्टियों से संबंधित सभी कानूनों वित्तियमों और अन्य विधियों का प्रशासन ।”;

(ख) उप शीर्ष “ख. व्यव विभाग” के नीचे प्रविष्टि 6 का लोप किया जाएगा ।

(ग) उप शीर्ष “ग. राजस्व विभाग” के नीचे :—

(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“1. (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड; और

(ii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सेवार्थी सभी मामलों ।”;

(ii) प्रविष्टि 4 में “स्टाम्पों” शब्द के स्थान पर “राजस्व स्टाम्पों” शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) प्रविष्टि 6 की उप प्रविष्टि (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(ख) अधीन, केनेबिस (भारतीय भांग) और अन्य स्थापक औषधियाँ और स्थापक पदार्थ ।”;

(iv) प्रविष्टि 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“7. औषधीय और प्रसाधन विनियम (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) का प्रशासन ।”;

(v) प्रविष्टि 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“8क. स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1965 (1965 का 61) का प्रशासन ।

9. स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन/करार और उनका कार्यान्वयन ।

10. सीमा-शुल्क (समुद्र, वायु और भूमि) जिसके अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), टैरिफ मूल्यांकन, सीमा-शुल्क सहकारिता परिपत्र, सीमा शुल्क नाम पद्धति और ऐसे ही मानने हैं, आयात या निर्यात किए गए माल पर शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन आयातों और निर्यातों पर प्रतिषेध और निर्यन्धन; और सीमा शुल्क टैरिफ का निर्यन्धन से संबंधित सभी मामलों ।”;

(vi) प्रविष्टि 13 का लोप किया जाएगा ।

(vii) प्रविष्टि 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“15. विदेशी मुद्रा के संरक्षण या संवर्धन और दम्परी क्रियाकलापों के निवारण और उससे संबंधित मामलों के प्रयाजनों के लिए निवारक निरोध ।”;

(viii) प्रविष्टि 16 में “राजस्व आसूचना महानिदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ix) प्रविष्टि 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“17. आर्थिक आसूचना ब्यूरो से संबंधित सभी मामलों ।

18. सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (निर्यन्धन) अधीन अधि-करण से संबंधित सभी मामलों ।”;

(ix) “खाद्य और नागरिक पुति संरक्षण” शीर्ष के नीचे,--

(क) उपशीर्ष “खाद्य विभाग” के नीचे,--

(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“1. निम्नलिखित आसूचनाओं के लिए खाद्य पदार्थ और सैनिक आवश्यकताओं के लिए चीनी, चावल, गेहूँ और गेहूँ के उरानों का वन और उनका निपटारा ।”;

(ii) प्रविष्टि 7क का लोप किया जाएगा ।

(iii) प्रविष्टि 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“11क. निम्नलिखित अधिक सैक्टर संगठनों से संबंधित मामलों--

(i) भारतीय खाद्य निगम ।

(ii) राष्ट्रीय माण्डानार निगम ।

(iii) माउन्टेन फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड ।

(iv) उपर्युक्त प्रदेशों की इण्डिया इण्डिया निगम लिमिटेड ।”

(iv) प्रविष्टि 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“16क. समुदाय और संरक्षित खाद्य पदार्थों का विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाना ।

(ख) पोषण का विस्तारण ।”;

(ख) उपशीर्ष “ख. नागरिक पुति विभाग” के नीचे प्रविष्टि 15 का लोप किया जाएगा ।

(v) शीर्ष “गृह संरक्षण” के नीचे,--

(क) उपशीर्ष “क. आंतरिक सुरक्षा विभाग” के नीचे,--

(i) प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“3क. आसूचना ब्यूरो, समन्वय खंड, केन्द्रीय न्याय विज्ञान प्रयोग-शाला, नई दिल्ली और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का केन्द्रीय अगुलियाय ब्यूरो ।”;

(ii) प्रविष्टि 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“6क. अग्निशमन सेवा का विस्तार ।”;

(iii) प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“10क. राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड ।”;

(iv) प्रविष्टि 13 और 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“13. दिल्ली तथा राज्य क्षेत्र के लिए लोक व्यवस्था (किंतु इसके अंतर्गत संघ के निपटणाधीन नौसेना, सेना, या वायुसेना या कोई अन्य सशस्त्र बल या सशस्त्र शक्ति की सहायता में उसका कोई दस्ता या एकक नहीं आता है) ।”;

(v) प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“19क. विदेशी अग्निशमन (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) का प्रवर्तन ।”;

(vi) प्रविष्टि 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

“20. आतंकवादी गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) का प्रवर्तन ।”;

(vii) प्रविष्टि 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“22 सीमा-गुन्थ अधिनियम 1962 (1962 का 57) की धारा-11 के अधीन भारत में अवाञ्छनीय साहित्य लाना या निर्यात।”

(viii) प्रविष्टि 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

‘25क विधि विरुद्ध विरोधवाक्य (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) का प्रवर्तन।’,

(ix) प्रविष्टि 31 का लाभ किया जाएगा।

(x) प्रविष्टि 37 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

‘37क श्री एका संज्ञा शरणाधिकार के लिए संहिता प्रसुविधान।’

(ख) उपरोक्त ख गण्ड विभाग के नीचे—

(i) प्रविष्टि 4 की उप प्रविष्टि (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपप्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“(1) दिल्ली मध्य राज्य क्षेत्र के निवाय लोक व्यवस्था (किन्तु इसके अन्तर्गत सिविल शक्ति की सहायता में सशस्त्री सेना, सेना, या वायु सेना का प्रयोग नहीं आता है)”

(ii) प्रविष्टि 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

‘9क. भारतीय सीमांत प्रशासनिक सेवा।’

(xi) “मानव संपन्न विकास मंत्रालय” शीर्ष के नीचे,—

(क) “क शिक्षा विभाग उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 51 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

‘52 आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए योजनाएँ”,

(ख) “घ संस्कृति विभाग”, उप-शीर्ष के नीचे,—

(i) प्रविष्टि 1 में “विक्टोरिया स्मारक” शब्दों के पश्चात् “एशियाटिक साम्राज्यी, कलकत्ता” शब्द अन्तस्थापित किए जायेंगे,

(ii) प्रविष्टि 1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

‘1 क राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ”,

(iii) प्रविष्टि 12 में, ‘राष्ट्रीय चित्र दंघा’ शब्दों के पश्चात्, ‘राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, नई दिल्ली, सांस्कृतिक स्नात और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता और इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद,” शब्द अन्तस्थापित किए जाएंगे,

(iv) प्रविष्टि 20 का लाभ किया जाएगा”,

(xii) ‘उद्योग मंत्रालय’ शीर्ष के नीचे,—

(क) “क. औद्योगिक विकास विभाग,” उप-शीर्ष के नीचे,—

(i) प्रविष्टि 21 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद्”

(ii) प्रविष्टि 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“23 तकनीकी विकस, इसके अन्तर्गत तकनीकी विकास मन्त्रालय, औद्योगिक मन्त्रालय और कीमत व्यूरो और मयूकन राज्य औद्योगिक विकास मण्डल भी हैं”;

(iii) प्रविष्टि 29 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

‘29 क आपात प्रारण वस्तु विरुद्ध अधिनियम, 1958 (1958 का 13)”,

(ख) ‘ख. कम्पनी काय विभाग उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तस्थापित की जाएगी अर्थात्—

‘9 केन्द्र प्रशासन क्षेत्र में मातृश्री रजिस्ट्रार अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन सहायक रजिस्ट्रार और कल्याण प्रयोग में मातृश्री वगैरह”,

(i) ‘घ सरकारी उद्यम विभाग उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 18 का लाभ किया जाएगा,

(xiii) “श्रम मंत्रालय” शीर्ष के अधीन भाग V के नीचे, प्रविष्टि 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“25 उत्प्रेषण अधिनियम, 1983 (1983 का 31) के अन्तर्गत भारत से विदेशों की सभी उत्प्रेषण और उत्प्रेषणियों का वापसी”;

(xiv) “विधि और न्याय मंत्रालय” शीर्ष के अधीन “क विधि कार्य विभाग” के नीचे,—

(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“1. अधिक मामलों पर मन्त्रालयों को सलाह देना जिसके अन्तर्गत संविधान और विधियों का निर्वाचन हस्तान्तरण लेखन, और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में जहाँ भारत मध्य एक पक्षकार है भारत मध्य की ओर से उप-मजालत होने के लिए काउन्सेल का नियोजन है;

(ii) प्रविष्टि 3 में, “उच्चतम न्यायालय” शब्दों के पश्चात्, “और उच्च न्यायालय” शब्द अन्तस्थापित किए जायेंगे,

(iii) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

‘9 विधिवत् वृत्ति विभाग के अन्तर्गत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) और उच्च न्यायालयों के समस्त विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति हैं”;

(iv) प्रविष्टि 10 में, “अनुपूरक” शब्द के स्थान पर, “अतिरिक्त” शब्द रखा जाएगा,

(v) प्रविष्टि 11 और 13 का लाभ किया जाएगा;

(xv) “संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय” शीर्ष के नीचे ‘क, संसदीय कार्य उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 16 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“17. संसद में विपक्षी नेता बैठन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33),

18. संसदीय मंच—कृत्य”;

(xv) विद्यमान शीर्ष ‘कामिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेशान मंत्रालय” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्—

“कामिक और शिकायत तथा पेशान मंत्रालय”,

(ख) "ग. उप-शीर्ष पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग" के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्—

"1. नीति बनाना और राष्ट्रीय सरकार के कर्मचारियों (सिविल, ग्लो और रेल पेंशनभोगियों) के लिए सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों का मसौदा करना।

2 निम्नलिखित का प्रशासन—

(i) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन साराणीकरण) नियम, 1981, केन्द्रीय सिविल सेवा (प्रसाधारण पेंशन) नियम, 1939, अखिल भारतीय सेवा (सूच्य तथा सेवा निवृत्ति प्रमृविधाएँ) नियम 1958, और

(ii) विभाग को सौंपा गई केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित कोई अन्य स्कीम।

3. पेंशन ढांचा और पेंशनभोगियों की राहत,

4. केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को नई सुविधाएँ या अनुपंगी हितलाभ;

5. पेंशन नियमों या सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित किसी अन्य नियमों के संशोधन या शिथिलीकरण से संबंधित मामले।

6. केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण से संबंधित नीति और समन्वय।

टिप्पण—उपर्युक्त 3 के संबंध में तारवाही वित्त मंत्रालय की सहमति से की जाएगी। अन्य मामले जिनमें अगली वित्तीय तिथितार्थ निहित हो के संबंध में तारवाही के किंगी नियम के शिथिलीकरण या उद्घारीकरण का कार्रवाई उन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते की जाएगी जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और वित्त मंत्रालय के व्यापक मामलों के बीच करार पाए हों।

(xvii) "योजना मंत्रालय" शीर्ष के अधीन "ग. सांख्यिकी विभाग" उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"3. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन।

(xviii) "हरपात और खान मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "क. हरपात विभाग" उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 8 की उप-प्रविष्टि (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"(1) विश्वेश्वरयया आयरन एंड स्टील लिमिटेड";

(xix) "परिवहन मंत्रालय" शीर्ष के अधीन,

(ग) 'क. रेल विभाग' उप-शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्—

"क. रेल विभाग, रेल बोर्ड"

(ख) "क. रेल विभाग, रेल बोर्ड" उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतर्स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"4. रेल कर्मचारियों को लागू पेंशन नियमों का प्रशासन";

(ग) "ख. नागर विमानन विभाग" उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 15 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतर्स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"16. भारतीय हेलीकोप्टर का नियम";

(घ) "ग. जल भू-तल परिवहन विभाग" उप-शीर्ष के नीचे—

(i) प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"1. भारतीय पत्तन शिपयार्ड, 1908 (1908 का 15) का प्रशासन और उस अधिनियम के अधीन मरुपत्तन के रूप में घोषित पत्तन।

(ii) प्रविष्टि 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"1. मुख्य शिपिंग और डंपिंग के बीच परिवहन सेवाओं का संचालन और प्रशासन।"

(iii) प्रविष्टि 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"19. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण या अंशतः वित्तपोषित मरुपत्तन संकर्मों के प्रशासन संबंधित नीतियों की छठी अनुसूची के पैरा 20 में सतत सारणी के भाग I और II में विनिर्दिष्ट, अंशतः केन्द्रीय क्षेत्रों में प्रांतीय मरुपत्तन और मरुपत्तन संकर्म हैं।"

(iv) प्रविष्टि 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतर्स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"28. राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध मंडल।

29. जल पत्तन सर्वेक्षण संगठन।

30. भारतीय पोत परिवहन नियम।

31. मुगल नाइन लिमिटेड।

32. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड।

33. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड।

34. भारतीय जमाई नियम।

35. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन विभाग।

36. भारतीय मरुपत्तन संनिर्माण नियम।

37. दिल्ली परिवहन नियम।"

(XX) "परमाणु ऊर्जा विभाग" शीर्ष के नीचे प्रविष्टि 11 में, "न्यूक्लीय शक्ति" शब्दों के पश्चात्, "और अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं" शब्द अंतर्स्थापित किए जायेंगे।"

जैल सिंह,

राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/85-मन्त्रि०]

एल.आर.के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1985

S.O. 893(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Seventy-seventh Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) In the First Schedule,—

- (i) for the heading "1.8 Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pension (Karmik aur Prashikshan, Prasasanik, Sudhar aur Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—

"18. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Karmik, Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya).";

- (ii) under the heading "24. Ministry of Transport (Pariwahan Mantralaya)", for the sub-heading "(1) Department of Railways (Rail Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely :—

"(i) Department of Railways (Rail Vibhag) Railway Board (Rail Board).";

(2) In the Second Schedule,—

- (i) under the heading "Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A. Department of Agriculture and Cooperation (Krishi Aur Sahkarita Vibhag)",—in Part IV, in entry 44, the words "and Forestry Development" shall be omitted.

(b) under the sub-heading "B. Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan Aur Shiksha Vibhag)",—

- (i) in Part I— in entry 1, for the words "Relations with foreign and international agricultural research", the words "International cooperation in the field of agricultural research and education including relations with foreign and international agricultural research" shall be substituted;

- (ii) in entry 2, after the word "higher education in agriculture", the words "including agro forestry" shall be inserted.

(c) under the sub-heading "C. Department of Rural Development (Gramin Vikas Vibhag)", after entry 19, the following entry shall be inserted, namely :—

"19A. Road works financed in whole or in part by the Central Government in tribal areas of Assam specified in Part I and Part II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.";

- (ii) under the heading "Ministry of Commerce (Vanijiya Mantralaya)", for the entries under the sub-heading "B. Department of Supply (Poorti Vibhag)", the following entries shall be substituted, namely :—

"1. Purchase and/or inspection of stores for Central Government Ministries/Departments including their attached and subordinate offices and Union territories, other than the items of purchase and inspection of stores which are delegated to other authorities by general or special order.

2. Purchase and/or inspection of stores on behalf of those State Governments, public undertakings, autonomous bodies, quasi-public bodies, etc. who desire to avail of its services.

3. To arrange payment for supplies made against contracts placed by the Department (DGS&D) on behalf of the authorities referred to in 1 and 2 above.

4. To arrange clearance of stores imported against orders placed by the Department and also orders placed by the other Central Government Departments State Governments, autonomous bodies, etc. if called upon to do so. To arrange shipment of stores against contracts placed by the Department wherever necessary or where such work is entrusted to the Department by other authorities.

5. Disposal of surplus stores other than those for which powers have been delegated to various authorities by general or special order.

6. Testing and evaluation of materials, products, equipments and systems; research and development in testing technology and related areas; and calibration in the level of Echelon II and maintenance of test data, etc.

7. Cadre Management of Indian Supply Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for the said service.

8. Cadre Management of Indian Inspection Services and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for the said service.

9. Administration of—

(a) Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi

(b) Office of the Chief Controller of Accounts, New Delhi

(c) National Test House, Alipore, Calcutta.";

(iii) under the heading "Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A. Department of Posts", in entry 3, for the words and brackets "Post Office Life Insurance Fund (Administration) and Broadcast Receiver Licence", the words and brackets "and Post Office Life Insurance Fund (Administration)" shall be substituted;

(b) under the sub-heading "B. Department of Telecommunications", for entry 4, the following entry shall be substituted, namely :—

"4. Indian Telephone Industries Limited, Bangalore the Hindustan Tele. Industries Limited Madras and the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi";

(iv) under the heading "Ministry of Defence (Raksha Mantralaya)",—

(i) under the sub-heading "A. Department of Defence (Raksha Vibhag)", after entry 13, the following entries shall be inserted, namely :—

"13. Defence Accounts Department.

15. Administration of—

(i) the Pension Regulations for the Army, 1961 (Parts I and II)

(ii) the Pension Regulations for the Air Force, 1961 (Parts I and II).

(iii) the Navy (Pension) Regulations 1964; and

(iv) the Entitlement Rules to Casualty Pensionary Awards to the Armed Forces Personnel, 1982.

16. Purchase of food stuffs for military requirements and their disposal excluding those entrusted to Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food).

17. Coast Guard Organisation":

(b) under the sub-heading "Department of Defence Production and Supplies (Raksha Utpadan Aur Poorti Vibhag)",—

(i) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"1. Ordnance Factory Board and Ordnance Factories.";

(ii) for entries 5 and 6, the following entries shall be substituted, namely :—

"5. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited.

6. Goa Shipyard Limited.

6A. Praga Tools Limited.

6B. Bharat Dynamics Limited.

6C. Mishra Dhatu Nigam Limited.

6D. Defence Inspection Organisation.

6E. Standardisation of defence equipment and stores.”;

(iii) in entry 8, for “Department of Atomic Energy (Parmatu Oorja Vibhag)”;

the following shall be substituted, namely :—

“Department of Space (Antariksh Vibhag)”;

(iv) for entries 9 and 10, the following entries shall be substituted, namely :—

“9. Indigenisation development and production of items required for defence purposes.

10. Procurement exclusive to the defence services.”;

(v) under the heading “Ministry of Energy (Qorja Mantralaya)”, under the sub-heading “B. Department of Power (Vidyut Vibhag)”, for entries 10 and 11, the following entries shall be substituted, namely :—

“10. Bhakra Beas Management Board and Beas Construction Board (except matters relating to irrigation).

11. National Thermal Power Corporation Limited.

12. National Hydro-electric Power Corporation Limited.

13. Rural Electrification Corporation Limited.

14. North Eastern Electric Power Corporation Limited.

15. Central Power Research Institute.

16. Power Engineers Training Society.”;

(vi) under the heading “Ministry of Environment and Forests (Paryavaran Tatha Van Mantralaya)”, after entry 16, the following entry shall be inserted, namely :—

“17. Financial Assistance to Forestry Development Schemes.”;

(vii) under the heading “Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya)”,—

(a) in entry 5, for the words “Ceylon nationals”, the words “Sri Lankan nationals” shall be substituted;

(b) in entry 11, the words “muleteers, porters” and the words “and vice versa” shall be omitted;

(c) in entry 19, for the words “and other International Conferences, the words “other International Organisations and Conferences” shall be substituted;

(d) in entry 25(a), for the words and figures “Port Haj Committee Act, 1932”, the words, brackets and figures “Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959)” shall be substituted;

(e) for entries 27, 28 and 29, the following entry shall be substituted, namely :—

“27. Questions relating to minority communities in neighbouring countries.”;

(viii) under the heading “Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)”,—

(a) for the entries under the sub-heading “A. Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)”, the following entries shall be substituted, namely :—

“I. Exchange Control

1. Administration of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) other than enforcement work mentioned under the Department of Revenue (Rajaswa Vibhag).

2. Foreign Exchange Budgeting.

239 GI/85—2.

3. Policy relating to exchange rates of Rupee.

4. Control of the foreign exchange resources including scrutiny of proposals for imports from the foreign exchange point of view.

5. Foreign and Non-Resident Indian Investment.

6. Approvals for commercial borrowing abroad, including terms and conditions therefor.

7. Import and Export of gold and silver.

II. Foreign aid for Economic Development.

8. All matters relating to :—

(a) India Consortium.

(b) Loans, credits and economic assistance from foreign countries.

(c) Loans and credits from International Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, Asian Development Bank, European Economic Community and Export-Import Banks, etc.

(d) Ford Foundation and Rockefeller Foundation.

(e) International Development Research Centre of Canada (IDRC).

(f) Commonwealth Fund for Technical Cooperation (CFTC).

9. Technical and economic assistance received by India under :—

(a) the Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan.

(b) the United States Point Four Programme.

(c) the United Nations Technical Assistance Administration Programmes.

(d) ad-hoc offers of technical assistance from various foreign countries.

10. Technical assistance given by India to the member countries of the Colombo Plan under Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan and technical assistance given by India to African countries under the Special Commonwealth African Assistance Plan programme.

11. All matters relating to the meetings of Colombo Plan Council and the Consultative Committee of the Plan.

12. All matters relating to credits extended by Government of India to other countries except Nepal, Bhutan and Bangladesh.

13. Technical assistance received by India or given to foreign governments, international institutions and organisations, except such as are relatable to subjects allocated to any other Department.

14. All matters concerning United Nations Development Programme (UNDP) including Programmes or Projects funded out of UNDP Budget.

15. Policy issues, relating to the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) and contributions to the specialised agencies of the United Nations and other U. N. Bodies.

16. All matters relating to the Foreign Volunteers Programmes in India including the United Nations Volunteers (except outgoing volunteers under UNV).

III. Internal Finance

17. all matters relating to currency and coinage, including:

(a) The Security and Currency Printing Presses, the Security Paper Mills and the Mints including the Assay Department and Silver Refinery, Gold Refinery and Gold collection-cum-delivery centres.

(b) Production and supply of Currency Note Paper, Currency and Bank Notes and Coins, postal stationery, stamps and various security forms.

18. Functions of the Treasurer of Charitable Endowments for India.

19. Administration of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

20. Regulation and development of Stock Exchanges.

21. Control over the Issues of Capital by Joint Stock Companies.

22. New Investments and Securities for mobilising resources from the Capital Markets.

23. Investment policy including investment policy of Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India and General Insurance Corporation of India.

24. Investment pattern for Employees' Provident Fund and other like Provident Funds.

IV. Budget

25. Ways and Means.

26. Preparation of Central Budget other than Railway Budget including supplementary/excess grants and when a proclamation by the President as to failure of Constitutional machinery is in operation in relation to a State or a Union territory, preparation of the Budget of such State or Union territory.

28. Market Borrowing Programme of Central and State Governments and Government Guaranteed Institutions.

28. Floatation of Market Loans by Central Government and issue and discharge of Treasurybills.

29. Administration of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944).

30. Fixation of interest rates for Central Government's borrowings and lending.

31. Accounting and audit procedures including classification of transactions.

32. Financial matters relating to Partition, Federal Financial Integration and Reorganisation of States.

33. Contingency Fund of India and Administration of the Contingency Fund of India Act, 1950 (49 of 1950).

34. Monitoring budgetary position of Central Government.

35. Sterling Pensions—Transfer of responsibility of U.K. Government and actual calculation of the liability involved.

36. Public Provident Fund Scheme.

37. Finance Commission.

38. Resources of Five Year and Annual Plans.

39. National Deposit Scheme, Special Deposit Schemes, Compulsory Deposit Scheme, other Deposit Schemes of Central Government.

40. Small Savings, including the administration of the National Savings Organisation.

41. Duties and powers of the Comptroller and Auditor General.

42. Laying of Audit Reports before the Parliament under article 151 of the Constitution.

43. Financial emergency.

V. Miscellaneous Acts

44. Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873).

45. Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) dealing with investments.

46. Metal Tokens Act, 1889 (1 of 1889).

47. Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890).

48. Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906).

49. Indian Securities Act, 1920 (10 of 1920).

50. Currency Ordinance 1940 (4 of 1940).

51. International Monetary Fund and Bank Act, 1945.

52. Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947).

53. Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951).

54. Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959).

55. Compulsory Deposit Scheme Act, 1963 (21 of 1963).

56. Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963).

57. Legal Tender (Inscribed Notes) Act, 1964 (28 of 1964).

58. Asian Development Bank Act, 1966 (18 of 1966).

59. Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968).

60. Small Coins (Offences) Act, 1971 (52 of 1971).

61. Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971).

62. Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974).

63. African Development Fund Act, 1982 (1 of 1982).

64. African Development Bank Act, 1983 (13 of 1983).

VI. Insurance Division

65. Policy relating to general insurance; administration of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972); Subsidiaries of the General Insurance Corporation.

66. Policy relating to life insurance; nationalisation of the Life Insurance Business; Administration of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956); Life Insurance Tribunal.

67. Controller of Insurance.

68. The responsibility of the Central Government relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the entries from 65 to 67 above.

VII. Management of the Indian Economic Service

69. Centralised aspects of managing the Indian Economic Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that service.

VIII. Economic Advice

70. Advice on matters which have a bearing on internal and external aspects of economic management including prices.

71. Credit, fiscal and monetary policies.

IX. Banking

72. All Indian banks, whether nationalised or not.

73. All foreign banks so far as their operations in India are concerned.

74. All matters relating to the Reserve Bank of India.

75. All matters relating to Cooperative Banking.

76. All matters relating to National Bank for Agriculture and Rural Development and long term financial institutions excluding Unit Trust of India, Life Insurance Corporation General Insurance Corporation.

77. Chit Fund and other non-banking companies accept-
ing deposits.

78. Other matters relating to Banking in India.

79. Administration of all statutes, regulation and other
laws connected with entries from 72 to 78."

(b) under the sub-heading "B. Department of Expendi-
ture (Vyaya Vibhag)", entry 6 shall be omitted.

(c) under the sub-heading "C. Department of Revenue
(Rajaswa Vibhag)",—

(i) for entry 1, the following entry shall be substituted,
namely :—

"1. All matters relating to—

(i) Central Board of Excise and Customs; and

(ii) Central Board of Direct Taxes."

(ii) in entry 4, for the word "stamps", the words "revenue
stamps" shall be substituted.

(iii) for sub-entry (b) of entry 6, the following sub-entry
shall be substituted, namely :—

"(b) Opium, Cannabis (Indian Hemp) and other Nar-
cotic Drugs and Narcotics" ;

(iv) for entry 7, the following entry shall be substituted,
namely :—

"7. Administration of the Medicinal and Toilet Prepara-
tions (Excise Drugs) Act, 1955 (16 of 1955)" ;

(v) for entries 9 and 10, the following entries shall be
substituted, namely :—

"8A. Administration of the Narcotic Drugs and Psy-
chotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985).

9. International Conventions/agreements relating to
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and
their implementation.

10 All matters relating to Customs (Sea, Air and Land)
including the Customs Tariff Act, 1975 (51 of
1975), Tariff Valuations, Customs Cooperation
Council, Customs nomenclature and similar matters
duties on goods imported or exported; prohibitions
and restrictions on imports and exports under the
Customs Act; and interpretation of Customs Tariff."

(vi) entry 13 shall be omitted.

(vii) for entry 15, the following entry shall be substituted,
namely :—

"15. Preventive detention for the purposes of conserva-
tion or augmentation of foreign exchange and pre-
vention of smuggling activities and matters connec-
ted therewith."

(viii) in entry 16, the words "the Directorate General of
Revenue Intelligence-cum-Directorate of Enforcement" shall
be omitted. ;

(ix) after entry 16, the following entries shall be inserted,
namely :—

"17. All matters relating to Economic Intelligence
Bureau.

18. All matters relating to the Customs Excise and Gold
(Control) Appellate Tribunal."

(ix) under the heading "Ministry of Food and Civil Supp-
lies (Khadya Aur Nagrik Poorti Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A. Department of Food
(Khadya Vibhag)",—

(i) for entry 1, the following entry shall be substituted,
namely :—

"1. Purchase of food stuffs for civil requirements
and their disposal and also for military require-
ments of sugar, rice, wheat and wheat produc-
tion";

(ii) entry 7 shall be omitted;

(iii) after entry 11, the following entry shall be inserted,
namely :—

"11A. Matters relating to the following public sector
organisations :—

(i) Food Corporation of India.

(ii) Central Warehousing Corporation.

(iii) Modern Food Industries (India) Limited.

(iv) North Eastern Regional Agricultural Marketing
Corporation Limited."

(iv) after entry 15, the following entry shall be inserted,
namely :—

"16(a) Development and popularisation of subsi-
diary and protective foods. ;

(b) Nutrition extension" ;

(b) under the sub-heading "B. Department of Civil
Supplies (Nagrik Poorti Vibhag)", entry 15 shall be
omitted. ;

(x) under the heading "Ministry of Home Affairs (Grih
Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A. Department of Internal
Security (Antrik Suraksha Vibhag)",—

(i) after entry 3, the following entry shall be inserted,
namely :—

"3A. Intelligence Bureau, Coordination Wing, Central
Forensic Science Laboratory, New Delhi and
Central Finger Print Bureau of the Central
Bureau of Investigation."

(ii) after entry 6, the following entry shall be inserted,
namely :—

"6A. Development of Fire Services." ;

(iii) after entry 10, the following entry shall be inserted,
namely :—

"10A. National Security Guard."

(iv) for entries 13 and 14, the following entry shall be
substituted, namely :—

"13. For the Union Territory of Delhi; Public
Order (but not including any naval, military or
air force or any other armed force subject to
the control of the Union or of any contingent
or Unit thereof in aid of civil power)." ;

(v) after entry 19, the following entry shall be in-
serted, namely :—

"19A. Enforcement of the Foreign Contribution
(Regulation) Act, 1976 (49 of 1976)";

(vi) for entry 20, the following entry shall be substi-
tuted, namely :—

"20. Enforcement of the Official Secrets Act, 1923
(19 of 1923).";

(vii) for entry 22, the following entry shall be substi-
tuted, namely :—

"22. Prevention of bringing into India of undesir-
able literature under section 11 of the Customs
Act, 1962 (52 of 1962).";

(viii) after entry 25, the following entry shall be
inserted, namely :—

"25A. Enforcement of the Unlawful Activities (Pre-
vention) Act, 1967 (37 of 1967).";

(ix) entry 34 shall be omitted;

- (x) after entry 37, the following entry shall be inserted, namely —
- “37A Relief facilities to refugees from Sri Lanka”,
- (b) under the sub-heading “B Department of States (Rajya Vibhag)”,—
- (i) for sub-entry (i) of entry 9, the following sub-entry shall be substituted, namely —
- “(i) Public Order (but not including the use of naval, military or air force of the Union in aid of civil power) except Union Territory of Delhi”,
- (ii) after entry 9 the following entry shall be inserted namely —
- “9A Indian Frontier Administrative Service”,
- (xi) under the heading “Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantraya)”,—
- (a) under the sub-heading “A Department of education (Shiksha Vibhag)”, after entry 51, the following entry shall be inserted namely —
- “52. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organisations for promotion of modern Indian languages”,
- (b) under the sub-heading ‘D Department of Culture (Sanskrit Vibhag)’,—
- (i) in entry 1, after the words, “the Victoria Memorial” the words “the Asiatic Society Calcutta” shall be inserted,
- (ii) after entry 1, the following entry shall be inserted, namely—
- “1A National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow”,
- (iii) in entry 12 after the words ‘National Gallery of Portraits,’ “the words “National School of Drama, New Delhi Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi, Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta and Allahabad Museum, Allahabad” shall be inserted
- (iv) entry 20 shall be omitted,
- (xii) under the heading “Ministry of Industry (Udvg Mantralaya)”,—
- (a) under the sub-heading “A Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag)”,—
- (i) for entry 21, the following entry shall be substituted, namely :—
- “21 National Council for Cement and Building Materials”;
- (ii) for entry 23, the following entry shall be substituted, namely —
- “23 Technical Development, including Directorate General of Technical Development, Bureau of Industrial Costs and Prices and United Nations Industrial Development Organisation”;
- (iii) after entry 29, the following entry shall be inserted, namely —
- “29A. Trade and Merchandise Marks Act 1958 (43 of 1958)”;
- (b) under the sub-heading “B. Department of Company Affairs (Kampani Karva Vibhag)”, after entry 8, the following entry shall be inserted, namely —
- “9. Legislation in relation to societies’ registration and exercise of functions under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in centrally administered areas”;
- (c) under the sub-heading “D Department of Public Enterprises (Sarkari Udyam Vibhag)”, entry 48 shall be omitted,
- (xiii) under the heading ‘Ministry of Labour (Sharam Mantralaya)’, under Part V for entry 25 the following entry shall be substituted, namely —
- ‘25 All emigration under the Emigration Act 1983 (31 of 1983) from India to overseas countries and the return of emigrants’,
- (xiv) Under the heading “Ministry of Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantralaya)” under the sub-heading “A Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag)”,—
- (i) for entry 1, the following entry shall be substituted namely —
- “1 Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyancing and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party”,
- (ii) in entry 3, after the words “Supreme Court” the words ‘and the High Courts’ shall be inserted,
- (iii) for entry 9, the following shall be substituted, namely—
- “9 Legal Profession including the Advocates Act 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts”,
- (iv) in entry 10 for the word “supplemental”, the word “further” shall be substituted,
- (v) entries 11 and 13 shall be omitted,
- (xv) Under the heading “Ministry of Parliamentary Affairs and tourism (Sansadiya Karya Aur Paryatan Mantralaya)” under the sub-heading “A Department of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Vibhag)”, after entry 16, the following entries shall be inserted, namely —
- “17. The Salary and Allowance of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977)
- 18 Parliamentary Secretaries—functions”,
- (xvi) (a) for the existing heading ‘Ministry of Personnel and Training Administrative Reforms and Public Grievances and Pension, (Karmik Shikayat aur Prashikshan Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat Tatha Pension Mantralaya)’ the following heading shall be substituted namely —
- ‘Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions (Karmik, Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya)’;
- (b) under the sub-heading “C Department of Pension and Pensioners’ Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag)”, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely —
- “1 Formulation of policy and co-ordination of matters relating to retirement benefits to Central Government employees (Civil, Defence and Railway Pensioners).
2. Administration of—
- (i) Central Civil Services (Pension) Rules, 1972; Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939, All India Services (Death-Cum-retirement benefits) Rules, 1958, and

(ii) any other scheme relating to Central Government pensioners, entrusted to the Department.

3. Pension structure and relief to pensioners.
4. New facilities or fringe benefits to the Central Government pensioners.
5. Matters relating to amendment to, or relaxation of Pension Rules or any other rule concerning retirement benefits.
6. Policy and co-ordination relating to welfare of Central Government pensioners.

NOTE . —The action in respect of 3 above shall be subject to the concurrence of Ministry of Finance. Action in respect of other matters involving recurring financial implications by way of relaxation or liberalisation of any rule shall be subject to guidelines, as agreed to between the Department of Pension and Pensioners' Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag) and the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya), Department of Expenditure (Vyaya Vibhag).";

(xvii) under the heading "Ministry of Planning (Yojana Mantralaya)", under the sub-heading "B. Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag)", for entry 3, the following entry shall be substituted, namely:—

"3. National Sample Survey Organisation.";

(xviii) under the heading "Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)", under the sub-heading "A. Department of Steel (Ispat Vibhag)", for sub-entry (1) of entry 8, the following sub-entry shall be substituted, namely:—

"(1) Visvesvaraya Iron and Steel Limited.";

(xix) under the heading "Ministry of Transport (Pariwahan Mantralaya)",—

(a) for the sub-heading "A. Department of Railways (Rail Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely:—

"A. Department of Railways (Rail Vibhag), Railway Board (Rail Board).";

(b) under the sub-heading "A. Department of Railways (Rail Vibhag), Railway Board (Rail Board)" after entry 3, the following entry shall be inserted, namely:—

"4. Administration of pension rules applicable to railway employees.";

(c) under the sub-heading "B. Department of Civil Aviation (Nagar Vimanana Vibhag)", after entry

15, the following entry shall be inserted, namely:—

"16. Helicopter Corporation of India.";

(d) under the sub-heading "C. Department of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Vibhag)",

(i) for entry 3, the following entry shall be substituted, namely:—

"3. Administration of Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and ports declared as major ports under that Act.";

(ii) for entry 16, the following entry shall be substituted, namely:—

"16. Organisation and maintenance of mainland-islands and inter-island shipping services.";

(iii) for entry 19, the following entry shall be substituted, namely:—

"19. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than rural roads and the road works in the tribal areas of Assam specified in Parts I and II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.";

(iv) after entry 27, the following entries shall be inserted, namely:—

"28. National Institute of Port Management.

29. Minor Ports Survey Organisation.

30. Shipping Corporation of India.

31. Mogul Line Limited.

32. Cochin Shipyard Limited.

33. Hindustan Shipyard Limited.

34. Dredging Corporation of India.

35. Central Inland Water Transport Corporation.

36. Indian Roads Construction Corporation.

37. Delhi Transport Corporation.";

(xx) under the heading "Department of Atomic Energy (Parmanu Orja Vibhag)", in entry 11, after the words "Nuclear Physics", the words "and other aided institutions" shall be inserted."

ZAIL SINGH, President

[No. 74/21/85-Cab]

L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.

